



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 326]
No. 326]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 1983/श्रावण 5, 1905
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 1983/SRAVANA 5, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1983

का० आ० 523 (अ) 18कक/आई० डी० आर० ए०/
83—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास
विभाग) के आदेश सं० का० आ० 265 (अ)/18कक/
आई० डी० आर० ए०/78, तारीख 13 अप्रैल, 1978
द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया
है), मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर
के सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रमों, अर्थात् (i) मैसर्स स्वदेशी
काटन मिल्स, कानपुर, (ii) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स,
पांडिचेरी, (iii) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, तैना, (iv)
मसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ भंजन, (v) मैसर्स
उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर और (vi) मैसर्स रायबरेली
टेक्सटाइल मिल्स, रायबरेली वा (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्
उक्त उपक्रम कहा गया है) प्रबन्ध, उद्योग (विकास और
विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की

धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन
13 अप्रैल, 1978 से पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण
किया गया था और नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड
को सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रमों का प्रबंध ग्रहण करने के लिए
प्राधिकृत किया गया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक
विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 283 (अ)/
18कक/आई० डी० आर० ए०/83, तारीख 11 अप्रैल,
1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 31 जुलाई, 1983
तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई
थी ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में
यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 जनवरी, 1984 तक
की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के
लिए प्रभावी बना रहे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और
विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की

धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 जनवरी, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे।

[फा० सं० 3(6)/78-सी० सू०एस०]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 27th July, 1983

S.O. 525(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by the Order of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 265(E)/18AA/IDRA/78 dated the 13th April 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the industrial undertakings, namely (i) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Kanpur, (ii) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Pondicherry, (iii) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Naini, (iv) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Maunath Bhanjan, (v) Messrs Udaipur Cotton Mills, Udaipur and (vi) Messrs Rae Bareilly Textile Mills, Rae Bareilly of Messrs Swadeshi Cotton Mills Company Limited, Kanpur (hereinafter referred to as the said undertakings) were taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years from the 13th April, 1978 and the National Textile Corporation Limited was authorised to take over the management of the whole of the industrial undertakings;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 283(E)/18AA/IDRA/83, dated the 11th April, 1983 the period of the said Order was extended upto and inclusive of the 31st July, 1983;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st January, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st January, 1984.

[File No. 3(6)/78-CUS]

फा० अ० 526 (अ)/18चख/आई० डी० आर० ए० 83—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० फा० आ० 277 (अ)/18चख/आई० डी० आर० ए०/78, तारीख 20 अप्रैल, 1978 द्वारा (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश समाहित किया गया है) केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व प्रेषित ऐसी सभी सविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, परिनिर्धारणों, पंचादों स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों से (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) जिनके सैमर्स स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड कानपुर के (i) सैमर्स स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर (ii) सैमर्स स्वदेशी काटन मिल्स, पाण्डिचेरी, (iii) सैमर्स स्वदेशी काटन मिल्स नैनी, (iv) सैमर्स स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ भंजन (v) सैमर्स उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर और (vi) सैमर्स रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स, रायबरेली नामक औद्योगिक उपक्रम पक्षकार हैं या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रमों का भाग हैं, से प्राप्ति या उद्भूत सभी बाध्यताओं और दायित्वों का प्रवर्तन ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निरविवश रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्राप्ति या उद्भूत सभी बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निरविवश रहेंगे।

और केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि जनसाधारण के हित के लिए यह आवश्यक है कि उक्त आदेश, पूर्वोक्त एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहना चाहिए; 31 जुलाई, 1983 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए ऐसे बने रहने की समय समय पर घोषणा की थी (देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय/औद्योगिक विकास विभाग के आदेश सं० फा० आ० 208 (अ)/18चख/आई० डी० आर० ए०/79, तारीख 16 अप्रैल, 1979, फा० आ० 262 (अ)/18चख/आई० डी० आर० ए०/80, तारीख 17-4-1980, फा० आ० 305 (अ)/18चख/आई० डी० आर० ए०/81, तारीख 20-4-81, फा० आ० 272 (अ)/18चख/आई० डी० आर० ए०/82 तारीख 20 अप्रैल, 1982 और फा० आ० सं० 284 (अ)/18चख/आई० डी० आर० ए०/83, तारीख 11 अप्रैल, 1983);

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 31 जनवरी, 1984 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए बड़ा दी जाना चाहिए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 51) की धारा 18चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश

की अवधि को 31 जनवरी, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए बढ़ाती है।

[फाइल सं० 3(6)/78 सी० यू० एम०]

ए० पी० सरवान, संयुक्त सचिव

S.O. 526(E)/18FB/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 277(E)/18FB/IDRA/78, dated the 20th April, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force, immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertakings known as: (i) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Kanpur, (ii) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Pondicherry, (iii) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Naini, (iv) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Mau-nath Bhanjan, (v) Messrs Udaipur Cotton Mills, Udaipur and (vi) Messrs Rae Bareli Textile Mills, Rae Bareli of Messrs Swadeshi Cotton Mills Company Limited, Kanpur are parties or which may be applicable to such industrial undertakings shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the obligations and liabilities accruing or arising

thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas the Central Government being of opinion that it is necessary in the interest of the general public that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of one year aforesaid, had declared from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st July, 1983 vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 209(E)/18FB/IDRA/79, dated 16th April, 1979, S.O. 262(E)/18FB/IDRA/80 dated the 17th April, 1980, S.O. 305(E)/18FB/IDRA/81 dated 20th April, 1981, S.O. 272(E)/18FB/IDRA/82 dated the 20th April, 1982 and S.O. No. 284(E)/18FB/IDRA/83 dated 11th April, 1983;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of the 31st January, 1984;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 31st January, 1984.

[File No. 3(6)/78-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

